MP Specific September Month Current Affairs

मध्य प्रदेश टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जायेगा

- मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की बड़ी सम्भावना है, प्रदेश में टेक्सटाइल हब बनाने की योजना है , इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे |
- टेक्सटाईल के क्षेत्र में सागर ग्रुप द्वारा प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें लगभग 4000 लोगों को सीधा रोजगार मिला है।
- यह ग्रुप प्रदेश में टेक्सटाईल सेक्टर, खाद्य प्र-संस्करण सेक्टर, रियल एस्टेट और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है।

मध्यप्रदेश में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा का प्रारंभ

- इंदौर से दुबई विमान सेवा प्रारंभ की गई , ग्वालियर से दिल्ली और इंदौर के लिए भी विमान सेवा शुरूआत की गई |
- इंदौर से पाँच और ग्वालियर से चार विमान सेवा आरंभ की गई हैं।
- इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने एवं एयरपोर्ट के विस्तार में राज्य शासन की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी |
- ग्वालियर में 500 करोड़ रूपये की लागत से नया भव्य हवाई अड्डा राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर स्थापित किया जाएगा। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन को 250 करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्वरूप दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण

- मध्य प्रदेश लोकसेवा संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भारी के पक्रम में आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है |
- यह 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है |

पैरा ओलम्पिक में मध्यप्रदेश की अवनी और को स्वर्ण पदक

- 30 अगस्त को अवनि लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पहला स्थान प्राप्त कर गोल्ड मैडल जीता था।
- अवनि को 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रांज मेडल मिला है |
- अवनि किसी ओलम्पिक या पैरालिंपिक्स में एक साथ दो पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है।
- टोक्यो पैरा ओलिंपिक में ऊँची कूद में श्री प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है |

byjusexamprep.com

मंडला के श्री शक्ति पटेल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2021 से सम्मानित

- मण्डला जिले के शिक्षक श्री शक्ति पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2021 से सम्मानित किया।
- श्री शक्ति पटेल मंडला जिले के ग्राम मांद के शासकीय हाई स्कूल में हिंदी विषय के माध्यमिक शिक्षक हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया तथा क्यूआर कोड द्वारा निःशुल्क नोट्स बच्चों को वितरित किए।
- इनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मनोरंजक शिक्षण सामग्री से देश के हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

आजादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न समारोह जबलपुर में आयोजित

- आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 18 सितम्बर को जबलपुर में बहुआयामी समारोह किया गया । इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह सम्मलित रहे ।
- जबलपुर में इस समारोह में आदिवासी जननायक शंकरशाह और रघुनाथ शाह के बलिदान का स्मरण किया गया । उनके बलिदान की गाथा की गीत-संगीतमय प्रस्तुति दी गई ।
- आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजाति नायकों के इस गौरव समारोह में प्रदर्शनी, पुस्तक लोकार्पण, फिल्म प्रदर्शन और ई-एलबम के लोकार्पण किया गया |
- समारोह में अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पर केन्द्रित फिल्म का प्रदर्शन किया गया |
- 'जंगे-ए-आज़ादी में जबलपुर' पुस्तक का विमोचन किया गया, स्वाधीनता संग्राम के रणबांकुरों, जननायकों तथा सेनानियों पर केन्द्रित ई-एल्बम का लोकार्पण भी किया किया गया ।

बैकलाग और निःशक्तजन के रिक्त पद विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की वृद्धि

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम में संशोधन

- मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम-14 के बाद 14 (अ) जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया है |
- इस नियम के अतंर्गत अभ्यर्थी से नियमित नियुक्ति के समय इस आशय का रुपये 5 लाख का बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा कि उसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएँ देना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएँ नहीं देने पर उक्त राशि या 3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, देना होगी।
- उक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में बांड की पूरी राशि राजसात की जा सकेगी।

- यदि आवेदक केन्द्र या मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय सेवा के लिए पूर्व अनुमति के साथ त्यागपत्र देता है ,तो उसे बंधपत्र की राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं है |

एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता योजना

- एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
- पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रूपये प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से 7 वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी।
- इकाइयों के लिए भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- उद्योग के लिए निजी/ आवंटित अविकसित शासकीय भूमि पर पानी/बिजली/सड़क अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत, जो प्रत्येक मद के लिये अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी, भोपाल नोडल एजेंसी होगी।

निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर को विधानसभा क्षेत्र बनाया जायेगा

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निवाडी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आदर्श बनाने की घोषणा की गई है।
- किसानों के लिये पृथ्वीपुर में नई मंडी शुरू की जायेगी। साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के भी प्रयास होंगे।

प्रदेश में प्रत्येक गरीब के लिए पक्का आवास

- वर्ष 2011 की सर्वे सूची में छूटे गरीबों का सर्वे किया जायेगा जिसमे पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे तथा उन्हें आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रूपये की राशि दी जायेगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पक्के मकान बना के दिए जा रहे है|
- प्रदेश के हर 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खोले जायेंगे। इनमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला सहित सभी सुविधाएँ होंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्य तथ्य :-

- यह योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई , जिसमे वर्ष 2022 (आजादी के 75 वर्ष पूर्ण) तक प्रत्येक परिवार को पक्का घर बना के देने की घोषणा की गई थी |
- इसके अंतर्गत पक्के मकान , पानी और बिजली की उपलब्धता प्रत्येक हितग्राही परिवार को कराई जाएगी |

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आरम्भ

- 16 सितंबर को इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की गई जिसमे लगभग 11 हजार करोड़ रुपए लागत अनुमानित की गई हैं ।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भारत माला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग मध्यप्रदेश सहित देश के पाँच राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा।
- परियोजना का 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्यप्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करेगा।
- यह एक्सप्रेस-वे मध्यप्रदेश के विकास में लाभकारी होगा। प्रदेश के सीमावर्ती जिले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर के साथ उज्जैन, इंदौर भी दिल्ली और मुम्बई से सीधे जुड़ सकेंगे।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया , इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में 5 लाख माताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार के वर्ष 2014 के **प्रथम** कार्यकाल से ही ग़रीब-कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को कियान्वित किया जा रहा है।
- **स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन**" स्लोगन के साथ केंद्र सरकार नें 1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना - "**प्रधानमंत्री उज्जवला योजना**" की शुरूआत की गई ।

स्वास्थ्य संस्थाओ को (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदंड अनुसार) विकसित करने में प्रदेश पुरुस्कृत

- प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स मापदण्ड (N Q A S) अनुसार विकसित करने पर प्रदेश पुरस्कृत हुआ। देश में प्रदेश को रनर-अप पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
- ''विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह'' लक्षित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर मेटरनिटी ओटी के क्वालिटी मानक की पूर्ति के आधार पर पुरस्कार दिए हैं।
- इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रसव कक्ष और प्रसूति आपरेशन थियेटर में प्रसव के दौरान उत्कृष्ट स्तर पर सभी मानकों के अनुसार उचित देखभाल करना है।
- इससे मातृ और नवजात मृत्यु दर को शून्य करना और मां बच्चे की उचित देखभाल सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश शामिल

- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से भारत के ग्रामीण समाज का विकास और प्रगति से सीधे जुडने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- योजना में ट्रायल के तौर पर जिन 6 राज्यों का चयन किया गया है, उसमें मध्यप्रदेश भी है।
- पूरे प्रदेश के किसान इस योजना से अधिक से अधिक लाभान्वित हो, इसके लिए हम लगातार समन्वय और प्रशासनिक सुदृढ़ता से काम कर रहे है।
- इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मज़बूत करना है, जिससे देश के बड़े बाज़ारों तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

मध्यप्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर

- मध्यप्रदेश ने डिजिटल एग्रीकल्चर यानि फसलों की पैदावार बढ़ाने और कृषि को सक्षम एवं लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और सेवाओं का इस्तेमाल लगातार बढ़ाया है।
- खेती में उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए मध्यप्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर अंतर्गत लगातार काम किया जा रहा है।
- कृषि को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से लाभदायक और टिकाऊ बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग करना डिजिटल कृषि कहलाता है।

"एक जिला-एक उत्पाद" योजना

- 1 नवम्बर म.प्र. स्थापना दिवस पर "एक जिला-एक उत्पाद" योजना प्रारंभ की ज जाएगी इसमें प्रत्येक जिला अपनी उत्पादक उपलब्धि का प्रदर्शन करे।
- मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में कुछ विशेष उत्पादन होते हैं। किसी जिले में काष्ठ शिल्पियों द्वारा, किसे जिले में बुनकरों द्वारा, तो किसी जिले में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण से जुड़े कार्य बड़े पैमाने पर होते हैं।
- "एक जिला-एक उत्पाद'' योजना में सभी जिलों के 64 उत्पादों का चयन कर लिया गया है।
- साथ ही जिले के प्रमुख उत्पाद के अलावा अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य भी हो इस योजना में शामिल है ।

किसानो को लाभान्वित करने हेतु बीजग्राम की शुरुआत

- मध्यप्रदेश में कृषि विभाग के बीज ग्रामों का शुभारंभ होगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
- इसमें प्रत्येक बीज ग्राम में 50 हितग्राही किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध किये जायेंगे।

- बीज मिनीकिट में उच्च उत्पादन किस्मों के बीज होंगे। इनसे कृषक नवीन किस्मों को अपनाये जाने के लिये प्रेरित होंगे। नवीन किस्मों के प्रमाणित बीज सीधे कृषकों तक पहुंचेंगे, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा|

प्रदेश में निर्यात बढ़ाने हेतु डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब का आरम्भ

- प्रदेश के प्रत्येक जिले में निर्यात से सम्बंधित कार्य हेतु राज्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रत्येक जिले में गठित की जाएगी |
- एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी।
- प्रदेश में एम.पी. ट्रेड पोर्टल और एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया |
- मध्यप्रदेश ट्रेड पोर्टल औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों के लिए निर्यात से जुड़ी तकनीकों को समझाने और निर्यातकों को विश्व के प्रमुख आयातकों से जोड़ने में सेतु का कार्य करेगा।
- निर्यातकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण एक्सपोर्ट हेल्पलाइन के माध्यम से किया जा सकेगा।
- निर्यात की संभावनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सर्वेक्षण और उत्पादन की माँग के आधार पर एवं उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उत्कर्ष वैल्यू चेन विकसित की जाएगी।

सार्वजानिक वितरण प्रणाली में 1 रुपए प्रति किलो की दर से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जायेगा

- यह एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा |
- सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का प्रारंभ किया गया जिसमे फोर्टिफाइड चावल एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- फ़ूड (खाद्य) फोर्टिफिकेशन को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और पोषण अभियान के माध्यम से एनीमिया को कम करने के लिए एक कम लागत वाले प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है।

संबंधित तथ्य :-

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार फोर्टिफिकेशन का मतलब है भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) की सामग्री को बढ़ाना। ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो शरीर को वे पोषक तत्व मिल पाएं जो कि कुपोषण को दूर करे। इसे आसान शब्दों में समझें तो, इसमें अनाज को पीस कर ऊपर से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसी तर्ज पर राइस फोर्टिफिकेशन (rice fortification) में नियमित चावल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ये पोषक तत्व आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जोड़ा जाता है।

- चावल के फोर्टिफिकेशन में कोटिंग और डस्टिंग जैसे कई तकनीकों की मदद ली जाती है। जैसे कि अनाज को पीस कर उसनें ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। यही चावल के साथ भी किया जाता है। इसमें चावल को पीसकर पाउडर तैयार कर इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जोड़े जाते हैं। उसके बाद इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को फिर से चावल के आकार में बदला जा सकता है, जिसे 'फोर्टिफाइड राइस कर्नेल' कहा जाता है।
- इस परियोजना के तहत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को सामान्य चावल के साथ के अनुपात में मिलाया जाता है और इसके बाद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मिड डे मील के तहत लोगों में बांटा जाएगा।

मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास के नए आयाम

- प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समीप अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर 'टूरिज्म सर्किट' विकसित किए जा रहे हैं।
- ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्रामों को हेरिटेज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 1500 से अधिक होमस्टे विकसित किए जायेंगे।
- हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मे 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' श्रेणी में नामांकित किया गया है।
- 'वेलनेस टूरिज्म' के अंतर्गत प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

महिला स्व सहायत समूह को पोषण का दायित्व

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की आंगनवाड़ियों में गर्भवती/धात्री माताओं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं के लिए टीएचआर प्रदायगी का कार्य स्व-सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा किये जाने के लिए 7 टीएचआर संयंत्रों की स्थापना वर्ष 2018 में की गई |
- इसके अंतर्गत देवास, धार, होशंगाबाद, मण्डला, सागर, शिवपुरी एवं रीवा में संयंत्र स्थापित किए गए।
- इन सभी संयंत्रो के माध्यम से (भोपाल संभाग के जिले छोड़कर) प्रदेश के अन्य सभी जिलों में रेडी टू ईट टेकहोम राशन (टीएचआर) दिया जा रहा है।

रेत नियम में संशोधन किया गया

- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन किया |
- इसके तहत रूपये 250 एवं निविदाकृत रेत मात्रा का गुणनफल प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) निर्धारित किए जाएंगे।

जन निजी भागीदारी से सतगढ़ी में खेल ग्राम का होगा निर्माण

- ग्राम सतगढ़ी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्व सुविधा युक्त "खेल ग्राम" का जन निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण किया जायेगा |

20 हजार महिला स्व-सहायता समूहों को 250 करोड़ बैंक ऋण वितरण

- स्व सहायता मूहों को क्रेडिट लिंकेज के अन्तर्गत ढ़ाई सौ करोड़ रूपये का बैंक ऋण वितरित किये जायेंगे ।
- सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की 2 लाख 27 हजार 687 महिलाओं को 22 करोड़ 77 लाख रुपये का आहार भत्ता और बाढ़ पीड़ितों को 163 करोड़ 28 लाख रूपये राहत राशि के रूप में वितरित किये जायेंगे।
- विशेष पिछडी जनजातियों के लिये आहार अनुदान योजना शुरू की गई है। इन जनजातियों के परिवार 14 जिलों श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में निवास करते हैं। इन परिवारों के खाते में एक हजार रूपये प्रतिमाह मिल रहे हैं |

byjusexamprep.com